and Transfer (BOT) basis without any financial assistance from the Government of India. The Ministry of Surface Transport had to issue global tender notice for this purpose and as a result only one company viz., M/s. Videocon International is eligible for consideration for award of contract. In the meantime, Ministry of Surface transport is processing the proposal for obtaining Government India's approval for the project.

Allotment of Plots by GNA to Group Housing Societies

3945. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some land has been mutated in favour of GNA, after signing of MOUs with some cooperative housing socieites, offering developed plots in exchange of their land;

(b) whether the land of certain cooperative societies is located in urban areas, not attracting the provisions of Section 154 NPZA and LR Act;

(c) whether the GNA has issued allotment letters to some of the members of those societies; and

(d) if so, whether the GNA would issue allotment letters to all the members covered by the MOUs, if not, the detailed reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Financial Assistance to Karnataka for Rural Electrification

3946. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Karnataka has been provided with financial assistance for rural electrification during the last two years and also during the current year;

(b) if so, the amount of assistai provided during each year;

(c) the number of villages in the St which do not have electricity as on 25th August, 1996; and

(d) by when all the villages would provided with electricity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MIN TER OF STATE IN THE MINIST) OF NON-CONVENTIONAL ENERC SOURCES (DR. S. Venugopalacha; (a) Yes, Sir.

(b) As per available information, Ru electrification Corporation (REC) 1 provided following financial assistance Karnataka during the last two years a the current financial year for rural el trification works:

Year	Amount (Rs. in crore
1994-95	50.04
1995-96	68.71
1996-97 (Upto July, 96)	13.50

In addition, Rs. 5.88 crores were a provided as grant to Karnataka Electi ty Board during the last two years Kutirjyoti Programme.

(c) and (d) As per 1981 Census *Kar*nataka has already declared cent per c village electrification by electrifying 26 villages out of 27,028 villages. Out of remaining 545 villages, 4 villages has been merged in urban conglomeral and remaining 541 villages are right r not feasible for electrification.

उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड का विकास

3947. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह ः की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य उत्तराखंड क्षेत्र के विकास हेतु 4.70 करोड़ रुपये नि किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का जिलावार ब्यौरा ा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ्यमंत्री (श्री योगिन्द्र के० अलघ): (क) और ग) उत्तराखंड उपयोजना 1995-96 में उत्तर प्रदेश के ारखंड क्षेत्र के विकास कार्यकलापों के लिए राज्य ाना के 322.00 करोड़ और विशेष केन्द्रीय सहायता रूप में 225.00 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए 7.00 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। में से 1995-96 हेतु विशिष्ट स्कीमों के लिए निर्धारित ा, सिंचाई सुविधाओं के सुधार के लिए 10 करोड़ ये, दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 125 करोड़ रुपये और ऋषिकेश-जोशीमठ, बद्रीनाथ ा रोड के सुधार की स्कीम को जारी रखने के लिए)0 करोड़ रुपये हैं। उपर्युक्त निर्धारित स्कीमों के 96-97 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

3948. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह ने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई समेकित ग्रामीण ऊर्जा क्रम आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी

राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 तक एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में 61 ब्लाकों को मंजूरी दी। एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम ब्लाकों की जिलावार सूची विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम ब्लाकों में एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लगभग 643.14 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)
1993-94	149.21
1994-95	173.19
1995-96	320.74
	643.14

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन के कार्य को मध्य प्रदेश राज्य सहित चुनिंदा राज्यों में आरंभ किया गया है। राज्य सरकार ने चुनिंदा आई० आर० ई० पी० ब्लाकों में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित किया है। ये दोनों अध्ययन अभी चल रहे हैं।

विवरण

्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1986-87 से 1995-96 तक एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गये ब्लाकों का ब्यौरा

र सं०	ब्लाक का नाम	जिला
.	केसला	होशंगाबाद
.	दुर्ग	दुर्ग
.	गांधीवानी	धार
.	कोटा	बिलासपुर
.	कालापीपल	शालापुर
.	सिधी	सिधी